(ख) क्या यह सच है कि कुछ एकक बन्द पड़े हैं किन्तु उन्हें कोयला मिलता रहा है और उसे काला बाजार में बेचा जाता रहा है; यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है कि जितने कोयले की सप्लाई की गई उसके अनुपात में उसका उत्पादन भी हुआ या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । (नीचे देखिए)

(ख) पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान दिल्ली प्रशासन ने यह पता लगाने के लिये कि क्या कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, 350 इकाईयों की जांच की थी । यह मालूम होने पर कि 61 इकाईयां उन्हें आवंटित कोयले का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, उनके कोटा कार्ड रद्द कर दिए गए थे ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

विवरण

वर्ष	निम्न के लिये प्रायोजित इकाईयों की सं०		आदेशित मात्रा (रेक में)		वास्तविक प्राप्ति उपयोग (रेक में)	
	स्टीम कोक	हार्ड कोक	स्टीम कोक	हार्ड कोक	स्टीम कोक	हार्ड कोक
1983 .	225	415	157	36	24	11
1984 .	214	412	155	36	38	11
1985 .	211	450	152	18	42	11

Pollution of Ganga

*230. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Pollution Control Board, New Delhi, has made a study of the main sources of pollution of Ganga;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government are taking in the matter on the basis of the study?

THE PRIME MINISTER (SHRI RAJIV GANDHI): (a) The Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution had prepared a Basin|Sub-Basin inventory of water pollution. The main objectives were to collect detailed data relevant to water pollution and water use for the entire Ganga Basin including information on related subjects such as climate, land use, waste disposal etc.

(b) The major findings of the report, as far as pollution is concerned are as follows:—

(i) The main sources of pollution are urban liquid waste, industrial liquid waste, surface run-off from cultivated land and surface run-off from areas on which urban or industrial solid wastes are dumped.

(ii) Despite considerable amount of resilience of the river, the organic pollution load in the river is significantly high in certain stretches.

(iii) The probable number of coliform count, one of the parameters of river quality, shows considerable variation in certain stretches and also during different seasons of the year. It is very high in summer and also immediately after the monsoon.

(iv) It is estimated that the discharge of sewage from the towns along the banks of the river accounted for almost 75 per cent of the pollution principally from the Class-I cities (population more than a lakh).

(v) The overall ambient water quality needs upgradation in many segments to satisfy the requirements of present use.

(c) An action Plan was prepared in December, '84 for reduction and prevention of pollution from the municipal wastes in 27 Class-I cities situated on the banks of the river. Based on per capita costs for the types of schemes to be taken up, the cost of the programme was tentatively estimated to be about Rs. 250 crores. In February, '85 the Central Ganga Authority under the chairmanship of the Prime Minister to oversee the implementation of the Action Plan was set up. In June, 1985 the Ganga Project Directorate was set up in the Ministry of Environment & Forests to coordinate the implementation of the Ganga Action Plan. The Central Ganga Authority in its first meeting in October, 1985 approved a Works Programme in 27 Class-I towns at a national cost of Rs. 292.31 crores. The types of schemes to be taken up under the Action Plan may be broadly classified as follows:—

(1) Schemes for diversion/interception of waste water including renovation/installation of interceptors or pumping stations.

(2) Renovation and installation of Sewage Treatment Plants incorporating bio-energy and resource recovery processes where feasible.

(3) Other schemes including Low Cost Sanitation, river front development, as necessary, and biological conservation.

During 1985-86, an amount of Rs. 6.24 crores was made available to U.P., Bihar and West Bengal for execution of schemes in the three States. One scheme in Ram Nagar, near Varanasi, at a cost of Rs. 9.75 lakhs and most of the works at Hardwar-Rishikesh at a cost of Rs. 1.60 crores have also been completed.

As on 30th April, '86, 19 schemes in 14 towns of West Bengal, 8 schemes in Patna, and 21 schemes in Hardwar-Rishikesh, Kanpur, Allahabad and Varanasi are under execution at a total cost of Rs. 23.55 crores.

कम्प्यूटरों का उपयोग

*231. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
डा० बापू कालदाते :

क्या प्रधान मंत्री 28 नवम्बर, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1176 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन द्वारा भेजे गये हजारों कम्प्यूटर, जिनका कम्प्यूटर शिक्षा के लिये उपयोग किया जा रहा है, अंग्रेजी में हैं और वास्तविक उपयोग में लाये जाने वाले साइबर 810 और 830 भी अंग्रेजी में ही हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अभी तक यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है कि हिन्दी में कितने कम्प्यूटरों की आवश्यकता है और उन्हें उपयोग हेतु कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) कार्यक्रम के लिये ग्रेट ब्रिटेन से 900 माइक्रो कम्प्यूटर प्राप्त किये गये थे। ये कम्प्यूटर वर्ष 1984-85 के दौरान 250 माध्यमिक विद्यालयों तथा 42 संसाधन केन्द्र में प्रतिष्ठापित किये गये थे। इन माइक्रो कम्प्यूटरों की खरीद के समय ये केवल अंग्रेजी में ही कार्य कर रहे थे। किन्तु अब इन कम्प्यूटरों पर देवनागरी में इनपुट/आउटपुट को निष्पादन क्षमता स्वदेश में ही विकसित कर ली गई है। भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कंट्रोल डेटा कार्पोरेशन के साथ एक प्रौद्योगिकी से संबंधित